BRIDGE UP OF INFLATIONARY GAP

Inflationary gap को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषिय नीति तथा अन्य नीतियों का अनुसरण किया जा सकता है —

Monetary Measures :—

मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंक के द्वारा संचालित होता है इस नीति के अन्तर्गत ब्याज दर में परिवर्तन लाकर देश में विनियोग की मात्रा प्रभावित की जाती है। मौद्रिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित उपायों द्वारा I.G को दूर किया जाता है।

① Bank Rate

केन्द्रीय बैंक साख संकुचन के लिए बैंक दर में वृद्धि करती है जिसके फलस्वरूप वाणिज्य बैंको का ब्याज दर स्वत: बढ़ जाता है। जिसके फलस्वरूप साख महंगी हो जाती है और साख का संकुचन हो जाता है। विनियोग घट जाता है तथा I.G दूर हो जाता है।

② Open Market Operation

केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की नीति में selling operation की क्रिया को अपनाती है जिसमें प्रथम श्रेणी के बांड तथा securities को विक्रय किया जाता है फलस्वरूप जनता के पास से मुद्रा निकलकर केन्द्रीय बैंक के पास चली

जाती है तथा मुद्रा या साख का संकुचन हो जाता है और I.G. दूर हो जाता है।

(3) Variation in Reserve Ratio

प्रत्येक वाणिज्य बैंक को केन्द्रीय बैंक के पास कोष के रूप में कुछ नकद रखना होता है। केन्द्रीय बैंक Cash Reserve Ratio बढ़ा देती है। जिसके फलस्वरूप वाणिज्य बैंक में साख निर्माण करनेवाला कुल जमा में कमी हो जाता है। साख मुद्रा का संकुचन हो जाता है। फलतः I.G दूर हो जाती है।

Fiscal Measure –

राजकोषीय नीति के द्वारा जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के माध्यम से I.G. दूर किया जाता है।

(1) Taxation

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के द्वारा वस्तु बाजार एवं साधनों के बाजार में मौजूद Inflationary gap को दूर किया जा सकता है। Hansen ने पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता तथा वास्तविक आय को स्थिर मानकर निम्न सूत्रों की सहायता से I.G दूर करने की बात कही है —

$$Q_0 = \phi\left(\frac{P}{W}\right) \qquad \frac{dQ_0}{d\left(\frac{P}{W}\right)} > 0$$

$$D_0 = \gamma\left(\frac{P}{W}\right) \qquad \frac{dD_0}{d\left(\frac{P}{W}\right)} < 0$$

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण की मात्रा कम करनी चाहिए। अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती करने से मुद्रा चलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उपभोक्ता के आयशक्ति में कमी होगी तथा मुद्रा स्फीति नियंत्रित होगी।

③ Public Debt Management

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक ऋण की अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को अधिक से अधिक सार्वजनिक ऋण लेना चाहिए तथा उसे idle cash balance के रूप में रखकर मुद्रा के चलन को नियंत्रित करना चाहिए। सार्वजनिक ऋण पर दिये गए ब्याज की मांग निश्चित रूप से कर की मात्रा से कम होनी चाहिए। इस तरह से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा।

Other Anti-Inflationary Measures:-

मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य नीतियों के द्वारा वस्तु के नियंत्रण को प्रभावित कर मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है।

① Rationing and Quota

राशनिंग तथा कोटा के माध्यम से जनता

को आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती है। तथा मुद्रा स्फीति के प्रभावों को उचित वितरण प्रणाली से दूर कि जा सकती है।

② Price Control Policy

इस नीति के अन्तर्गत सरकार आवश्यक वस्तुओं का निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारित कर लेती है तथा सरकारी अधिकारी सदा इसका संरक्षण करते रहते है कि ये वस्तुएँ Regulated Price पर जनता को उपलब्ध है। Black Marketing Hoarding तथा Profitering के खिलाफ कानून पारित किये जाते है।

③ Saving Drive

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए आकर्षक बचत नीति अपना ली जानी चाहिए ताकि स्वैच्छिक तथा आवश्यक बचत की मात्रा बढ़े। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में excess demand में कमी होती है। और मुद्रा स्फीति नियंत्रित होती है।

Phillips Model

Phillips का कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था में I.G का कारण लागत बढ़ाना है मजदूरी तथा लाभ का बढ़ना है तो इस दशा में राजकोषिय नीति के द्वारा I.G को दूर नही

किया जा सकता है।

Phillips के अनुसार पूंजीवादी विकसित देश में मजदूरी लागत तथा कीमत के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। इसके अनुसार बेरोजगारी की मात्रा बढ़ाकर G.D. को हर किया जा सकता है।

Phillips के अनुसार

"It is only such percentage increase in the money wages which does not represent corresponding increase in labour productivity to match the increase in the money wages which is inflationary."

Conclusion

इसप्रकार G.D को हर करने के लिए एक साथ मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक नीति है। वितरण प्रणाली पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मजदूरी मूल्य तथा आय से संबंधित नीतियों के बीच सह संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।

Dr Sandhya Rai
Dept of Economics